

अध्याय 58

विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की परिकल्पना (The Rational Expectations Hypothesis)

1. प्रस्तावना (INTRODUCTION)

1930 के दशक में जब केन्ज ने अपना 'सामान्य सिद्धांत' लिखा तब विश्व की मुख्य समस्या बेरोजगारी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान स्फीति मुख्य आर्थिक समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। विश्वयुद्ध के उपरांत 1960 के दशक तक बेरोजगारी एक बार फिर आर्थिक समस्या बन गई। अगली एक दशाब्दी तक बेरोजगारी तथा स्फीति दोनों ने मिलकर एक नया रूप धारण कर लिया, जिसे गतिहीन स्फीति (stagflation) कहा गया। गतिहीन स्फीति की यह नई समस्या नीति-निर्धारकों तथा अर्थशास्त्रियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई, क्योंकि केन्ज का सिद्धांत इस विषय में मौन था। अतः इस संकटपूर्ण स्थिति से एक नये समष्टि आर्थिक सिद्धांत का जन्म हुआ, जिसे विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की परिकल्पना अर्थात् रेटेक्स (Ratex) का नाम दिया गया।

2. अनुकूली प्रत्याशाएं (ADAPTIVE EXPECTATIONS)

रेटेक्स परिकल्पना की चर्चा करने से पहले समष्टि अर्थशास्त्र में प्रयोग की गई अनुकूली प्रत्याशाओं के अर्थ को समझना आवश्यक है जिसका विकास रेटेक्स सिद्धांत से पहले हुआ था।

प्रत्याशाएं उन अनिश्चित आर्थिक चरों के संदर्भ में किसी आर्थिक एजेंट द्वारा किए गए पूर्वानुमान या भविष्यवाणियां होती हैं जो उसके निर्णय से संबद्ध होती हैं। पूर्वानुमान भूत (past) की प्रवृत्तियों के साथ-साथ वर्तमान सूचना एवं अनुभव पर आधारित होते हैं। आर्थिक सिद्धांत का मुख्य भाग आर्थिक एजेंटों (अर्थात् उपभोक्ता, उत्पादक आदि) द्वारा प्रत्याशाओं के निर्माण में उनके विवेकशील व्यवहार की मान्यता पर आधारित है। परन्तु अभी तक अर्थशास्त्री मानवीय व्यवहार के माप में प्रत्याशाओं को भूमिका को शामिल नहीं कर पाए हैं। केन्ज ने प्रत्याशाओं के महत्व की चर्चा की परन्तु वे इस बात पर चुप थे कि उनका निर्माण किस प्रकार होता है।

हाल के वर्षों में, अर्थशास्त्रियों ने मॉडल निर्माण में अनुकूली प्रत्याशाओं की परिकल्पना का व्यापक प्रयोग किया है। इस संदर्भ में 1956 में कैगन (Cagen) और 1957 में नेरलोव (Nerlove) द्वारा किया गया कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। अनुकूली प्रत्याशा परिकल्पना के अनुसार होगा। वे कीमत, आय जैसे आर्थिक चरों के भविष्य मूल्यों को उनके भूत मूल्यों के औसत के रूप में होने तथा बहुत ही धीमी गति से उनके परिवर्तित होने की प्रत्याशा करते हैं। आर्थिक एजेंट इन चरों के प्रत्याशित मूल्य को उनके वर्तमान एवं भूत मूल्यों के भारित (weighted) औसत के समान कर देते हैं। वे अपनी प्रत्याशाओं को पिछली पूर्वानुमान त्रुटि के अनुसार संशोधित करते हैं। पिछले व्यवहारों के परिणामस्वरूप हुई त्रुटियां प्रत्याशाओं के निर्माण के लिए सूचना के एक महत्वपूर्ण स्रोत का संकेत करती हैं। परन्तु ऐसी प्रत्याशाएं इस मान्यता पर आधारित होती हैं कि आर्थिक एजेंट उन भूलों में बहुत कम परिवर्तन होने की प्रत्याशा करते हैं। अतः जब आर्थिक नीति में परिवर्तन होता है तो इससे प्रायः निरर्थक पूर्वानुमान होते हैं।

उदाहरण के लिए, अनुकूली प्रत्याशा परिकल्पना के अनुसार आर्थिक एजेंट, भविष्य की स्फीति दरों की प्रत्याशाओं का निर्माण, पहले अनुभव हुई औसत स्फीति दरों के भारित औसत से करते हैं और यदि वास्तविक स्फीति प्रत्याशित स्फीति से भिन्न होने वाली होती

है तो वे समय-समय पर उन प्रत्याशाओं को संशोधित करते हैं। यह आर्थिक एजेंटों के अविवेकी (irrational) व्यवहार की प्रकृति का कारण है। दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का फ्रीडमैन का विश्लेषण अनुकूली प्रत्याशा परिकल्पना पर आधारित है। फ्रीडमैन की प्रत्याशा (acceleration) परिकल्पना में निहित मान्यता कि कीमत प्रत्याशाएं मुख्य रूप से पहले की स्थिति के अनुभव पर आधारित होती हैं, अवास्तविक है। जब आर्थिक एजेंटों की कीमत प्रत्याशाएं इस मान्यता पर आधारित होती हैं तो वे अविवेकी होते हैं। यदि वे पहले की कीमतों की स्थिति में ऐसा सोचते हैं तो अपने को गलत पाएंगे। इसका कारण है कि प्रत्याशाओं का निर्माण केवल पहले के प्रयोग (projections) से ही नहीं, बल्कि भविष्य के प्रत्यक्ष पूर्वानुमानों से भी होता है। लोगों की प्रत्याशाओं का आधार पिछले कीमत परिवर्तनों के साथ-साथ कई घटकों के संबंध में वर्तमान सूचनाएं भी होती हैं। इस प्रकार, विवेकशील लोग भविष्य की स्थिति का प्रत्यक्ष यथार्थता से पूर्वानुमान करने के लिए सभी उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग करते हैं।

3. विवेकपूर्ण प्रत्याशाएं (RATIONAL EXPECTATIONS)

विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं का विचार सर्वप्रथम जॉन मूथ द्वारा 1961 में प्रस्तुत किया गया, जिसने यह विचार इंजीनियरी साहित्य से लिया था। उसका मॉडल मुख्य बाजार की मॉडलिंग कीमत गतिविधियों के बारे में है। यदि हम यह मानकर चलें कि आर्थिक एजेंट प्रत्याशाओं का निर्माण करते समय सूचनाओं (informations) का कुशल व आदर्शतम उपयोग करते हैं तो वे प्रत्याशाओं के एक ऐसे मिश्रण का रचना करते हैं जिससे उपभोक्ता तथा उत्पादक के प्रत्याशित कीमत परिवर्तन पर आधारित प्रतिक्रिया उनके वास्तविक कीमत परिवर्तन पर आधारित प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। मूथ का कहना है कि कुछ प्रत्याशाएं इन अर्थों में विवेकपूर्ण हैं कि प्रत्याशाएं तथा घटनाएं एक अविवेकित (random) त्रुटि के कारण ही भिन्न होती हैं।

मूथ की विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की कल्पना व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। इससे बहुत से अर्थशास्त्री संतुष्ट नहीं थे। अतः वह दस वर्षों तक निष्क्रिय रही। 1970 के दशक के आरंभ में रॉबर्ट लूकस, थॉमस सारजेंट तथा नील वैलस ने इस पर विचार का उपयोग समष्टि अर्थशास्त्र नीति की समस्याओं के लिए किया।

4. विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की परिकल्पना की मूल प्रस्थापनाएं (BASIC PROPOSITIONS OF RATIONAL EXPECTATIONS HYPOTHESIS)

रेटेक्स परिकल्पना मानती है कि आर्थिक एजेंट अपने पास उपलब्ध समस्त आर्थिक सूचना का उपयोग करके कीमतों, आय आदि जैसे आर्थिक चरों (variables) के भावी मूल्यों की प्रत्याशाओं का निर्माण करते हैं। यह सूचना विशेषकर सरकार की मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों जैसे आर्थिक चरों से जुड़े हुए सम्बन्धों को अपने में सम्मिलित करती है। इस तरह प्रत्याशाएं बनाने वाले यह मानते हैं कि आर्थिक एजेंटों को भविष्य की घटनाओं के बारे में पूरी और सही सूचना मिलती है। मूथ के अनुसार, सूचना को किसी अन्य दुर्लभ संसाधन की तरह समझना चाहिए। इसके अलावा विवेकपूर्ण आर्थिक एजेंट अपनी प्रत्याशाएं बनाते समय आर्थिक प्रणाली के संबंध में अपने ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। अतः रेटेक्स की परिकल्पना यह मानती है कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट प्रत्याशाओं का निर्माण करने में संपूर्ण उपलब्ध और सुसंगत सूचना का उपयोग करते हैं और वे इस सूचना को अपने विवेक से तैयार करते हैं। यह मानना महत्वपूर्ण है कि रेटेक्स, उपभोक्ता अथवा फर्मों के पूर्णतः दूरदर्शी होने या उनकी प्रत्याशाएं हमेशा सही होने को प्रकट नहीं करता है। यह संकेत करता है कि एजेंट निम्नलिखित त्रुटियों पर विचार करते हैं और यदि आवश्यक हो तो ऐसी त्रुटियों को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने प्रत्याशित व्यवहार का पुनरोन्मुखण करते हैं। वस्तुतः ऐसे अनुमान यह संकेत देते हैं कि एजेंट नियमित प्रत्याशित त्रुटियों को दूर करने में सफल होते हैं ताकि उपलब्ध सूचना से ऐसे त्रुटियां औसतन असंबद्ध हों।

रेटेक्स परिकल्पना आर्थिक (मौद्रिक, राजकोषीय और आय) नीतियों पर लागू की जाती है। विवेकपूर्ण प्रत्याशाएं लगाने वालों ने स्थिरीकरण नीतियों की अल्पकालिक अप्रभावशीलता को प्रकट किया है। उनके अनुसार, आर्थिक (मौद्रिक, राजकोषीय और आय) नीतियों में परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभावों की अधिक सूचना किसी को भी नहीं होती। विशेषरूप से, इसका अर्थ मंदी को नियंत्रित करने हेतु समष्टि आर्थिक नीतियों जैसे कर कटौती करना, सरकारी खर्च बढ़ाना, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना या घाटे का

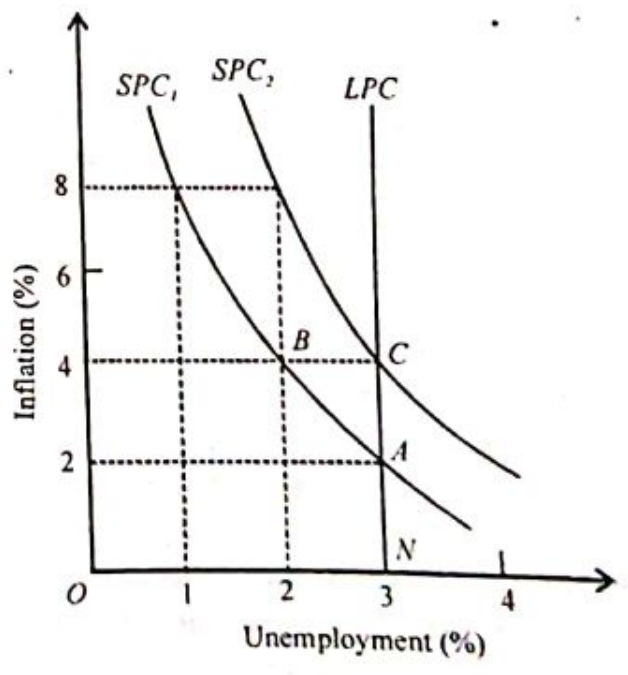
बजट बनाना आदि पर रोक लगाना है। उनका तर्क है कि जनता ने पिछले अनुभव से यह सीखा है कि सरकार ऐसी नीतियों का अनुसरण करेगी। इसलिए सरकार इनके प्रभावों को अपनाकर जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती और ऐसी नीति का संकेत मात्र भी जनता को राजकोपीय नीतियों के बारे में लोग अनुमान लगाते हैं और आर्थिक फैसले करते समय उनकी ओर ध्यान देते हैं। इसके परिणामस्वरूप, जब तक सरकारी नीतियों के संकेत मिलते हैं, जनता उन पर पहले से ही कार्य कर चुकी होती है और उनके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, रेटेक्स परिकल्पना यह बताती है कि लोगों के आर्थिक व्यवहार में वही नीति-चालें परिवर्तन लाती हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जाती है और वे सरकार द्वारा अप्रत्याशित चालें होती हैं। जब एक बार लोगों को नीति के बारे में सूचना प्राप्त हो जाती है और उसके चालू होने की प्रत्याशा होती है तो यह लोगों के आर्थिक व्यवहार में परिवर्तन ला सकती है।

विवेकपूर्ण प्रत्याशाएं और फिलिप्स वक्र
(Rational Expectations and the Phillips Curve)

फ्रीडमैन द्वारा प्रतिपादित फिलिप्स वक्र की त्वरित परिकल्पना (accelerationist hypothesis) में बेरोजगारी और स्फीति के बीच अल्पकाली विनिमय (trade-off) तो है परन्तु दीर्घकालीन विनिमय नहीं है। इसका कारण यह है कि स्फीतिकारी प्रत्याशाएं स्फीति की पिछली प्रवृत्ति पर आधारित होती हैं जिनकी भविष्यवाणी एकदम सही नहीं की जा सकती है। क्योंकि स्फीति की संभावित दर उसकी वास्तविक दर से हमेशा पीछे रहती है, इसलिए हमेशा एक अवलोकित (observed) त्रुटि पाई जाती है। स्फीति की संभावित दर को वास्तविक दर से समायोजित करने के लिए प्रथम अवधि में अवलोकित त्रुटि के कुछ अनुपात को जोड़कर पहली अवधि में होने वाली स्फीति के अनुभव अनुसार उसकी संभावित दर का पुनरीक्षण किया जाता है।

विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं से संबद्ध अर्थशास्त्रियों ने दीर्घावधि के दौरान भी स्फीति और बेरोजगारी के बीच विनिमय रहने की संभावना से इन्कार किया है। उनके अनुसार, फ्रीडमैन के इस कथन में अंतर्निहित यह धारणा अवास्तविक है कि कीमत प्रत्याशाएं मुख्यरूप से पिछली स्फीति के अनुभव के आधार पर ही बनाई जाती हैं। जब लोग अपनी कीमत प्रत्याशाओं को इस मान्यता के आधार पर रखते हैं तो वे अविवेकी होते हैं। यदि वे बढ़ती हुई कीमतों के दौरान ऐसा सोचते हैं तो यह पायेंगे कि वे गलत थे। परन्तु विवेकपूर्ण लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, बल्कि वे भावी स्फीति की अपेक्षाकृत अधिक सही भविष्यवाणी करने में समस्त उपलब्ध सूचना का प्रयोग करेंगे।

फिलिप्स वक्र के संबंध में विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं का विचार चित्र 1 में प्रस्तुत किया गया है। मान लीजिए कि बेरोजगारी की दर 3 प्रतिशत और स्फीति की दर 2 प्रतिशत है। हम SPC_1 वक्र पर बिन्दु A से प्रारंभ करते हैं। बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार मुद्रा पूर्ति की दर बढ़ा देती है, जिससे कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। रेटेक्स परिकल्पना के अनुसार, फर्मों की कीमतों के सामान्य स्तर की वजाय अपने उद्योग की कीमतों के बारे में अपेक्षाकृत अधिक सूचना उपलब्ध हैं। उनका यह सोचना मात्र एक भूल है कि कीमतों में वृद्धि उनकी वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण हुई है। इसके परिणामस्वरूप, उत्पादन बढ़ाने के लिए वह अधिक वर्कर्स कोरोजगार पर लगाते हैं, जिससे बेरोजगारी कम हो जाती है। वर्कर भी कीमतों में वृद्धि को अपने उद्योग से संबंधित मानने की भूल करते हैं। परन्तु जब श्रमिकों की मांग बढ़ती है तो मजदूरी बढ़ती है और वर्कर मौद्रिक मजदूरी की वृद्धि को वास्तविक मजदूरी की वृद्धि मान लेते हैं। इस तरह अर्थव्यवस्था अल्पकालीन फिलिप्स वक्र SPC_1 पर A बिन्दु से B बिन्दु पर ऊपर की ओर चलती है। परन्तु जल्दी ही वर्कर और फर्म यह पाते हैं कि सभी उद्योगों में कीमतों और मजदूरियों की वृद्धि हो गई है। यह भी पाती है कि उनकी लागतें बढ़ गई हैं। स्फीति दर में 4 प्रतिशत वृद्धि के साथ ही वर्कर यह महसूस करते हैं कि उनकी वास्तविक



चित्र 1

मजदूरियां कम हो गई हैं और वे मजदूरी बढ़ाने के लिए दबाव डालते हैं। इस प्रकार, सरकार की मुद्रा नीति के कारण अर्थव्यवस्था में स्फीति की दर बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप, SPC_2 वक्र पर यह बिन्दु B से C की ओर चला जाता है जहां बेरोजगारी दर 3 प्रतिशत है जो सरकार द्वारा विस्तारक मौद्रिक नीति अपनाने से पहले के बराबर है।

जब सरकार दोबारा मुद्रा-स्फीति बढ़ाकर रोजगार कम करने का फिर प्रयास करती है तो वह उन कर्मचारियों तथा फर्मों को मूख नहीं बना सकती जो अब अर्थव्यवस्था में लागतों व कीमतों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। यदि फर्म अपनी वस्तुओं की लागतों के साथ-साथ कीमतों में वृद्धि की आशा करती हैं तो वे अपना उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा नहीं करेंगी जैसाकि SPC_1 वक्र के मामले में हुआ। जहां तक वर्करो के प्रश्न हैं, श्रम संगठन अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई कीमतों के अनुसार मजदूरी बढ़ाने की मांग करेंगे। जब सरकार मौद्रिक प्रसारण (अथवा राजकोषीय) नीति को चालू रखती है तो वर्करो और फर्मों को इसकी आदत हो जाती है। उनका अनुभव ही उनकी प्रत्याशाएं बन जाता है। अतः सरकार जब दोबारा इस तरह की नीति अपनाती है तो फर्म अपनी वस्तुओं की कीमतें, प्रत्याशित स्फीति को बे-असर करने के लिए बढ़ा देती हैं ताकि उत्पादन तथा रोजगार पर इसका प्रभाव न पड़े। इसी प्रकार, स्फीति की प्रत्याशा में वर्कर अधिक वेतन की मांग करते हैं और फर्म अधिक नौकरियां नहीं देती हैं। दूसरे शब्दों में, फर्म तथा वर्कर मजदूरी समझौतों तथा कीमत-नीतियों में अपनी प्रत्याशाएं बना लेते हैं ताकि बेरोजगारी की वास्तविक दर तथा प्राकृतिक दर में, यहां तक कि अल्पकाल में भी, कोई अन्तर न रह जाए।

5. स्थिरीकरण नीति तथा रेटेक्स परिकल्पना (STABILISATION POLICY AND RATEX HYPOTHESIS)

रेटेक्स परिकल्पना के अनुसार, मौद्रिक और राजकोषीय (स्थिरीकरण) नीतियां अल्पकाल में अप्रभावी (ineffective) हैं, क्योंकि अल्पकाल के दौरान प्रत्याशाओं का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसे नीति नपुंसकता (असमर्थता) (policy impotence) कहा जाता है। रेटेक्स परिकल्पना इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता तथा फर्म आगामी आर्थिक गतिविधियों के बारे में सही जानकारी रखती हैं। इसीलिए उनकी प्रत्याशाएं विवेकपूर्ण होती हैं क्योंकि वे सभी उपलब्ध सूचनाओं, विशेषकर संभावित सरकारी कार्रवाईयों पर आधारित होती हैं। यदि सरकार किसी अनुकूल मौद्रिक अथवा राजकोषीय नीति का अनुसरण करती है तो लोग इसके बारे में जान जाते हैं और उसी के अनुसार अपनी योजनाओं का समायोजन (adjustment) कर लेते हैं। अतः जब भी सरकार कोई संभावित नीति अपनाती है तो वह प्रभावी नहीं होती, क्योंकि लोग इसका पूर्वानुमान लगाकर अपनी योजनाओं को इसी के अनुसार पहले ही समायोजित कर चुके होते हैं। इसका अर्थ है कि सरकारी नीति अप्रभावी है। एक अन्य महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि सभी बाजार पूरी तरह प्रतियोगी हैं तथा कीमतें तथा मजदूरियां पूरी तरह लोचपूर्ण हैं।

आइए पहले राजकोषीय नीति को ही लें। केन्ज के सिद्धांत को मानने वाले बेरोजगारी को कम करने के लिए एक सक्रिय (activist) राजकोषीय नीति की वकालत करते हैं। परन्तु रेटेक्स परिकल्पना के अनुसार कर में कटौती तथा / या सरकारी खर्च में वृद्धि बेरोजगारी को केवल तभी कम करेगी जब इसके अर्थव्यवस्था पर अल्पकालिक प्रभाव लोगों के लिए अप्रत्याशित (या अपूर्वानुमानित) हों। दूसरे शब्दों में, एक राजकोषीय नीति का बेरोजगारी को कम करने का अल्पकालिक प्रभाव हो सकता है, यदि लोगों को यह पूर्वानुमान न हो कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी। परन्तु जब कभी सरकार किसी ऐसी नीति पर डटी रहती है तो लोगों को स्फीति दर बढ़ने की आशा हो जाती है। अतः स्फीति में वर्कर भावी वृद्धि की सम्भावना को देखते हुए अधिक मजदूरी की मांग करेंगे तथा फर्म भविष्य में होने वाली लागतों में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हुए अपनी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करेंगी। इसके परिणामस्वरूप राजकोषीय नीति अल्पकाल में अप्रभावी हो जाएगी। इससे दीर्घकाल में बेरोजगारी और स्फीति बढ़ सकती है जब सरकार स्फीति को नियन्त्रित करने का प्रयास करती है।

इसी प्रकार, यदि सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए विस्तारक मौद्रिक नीति द्वारा मुद्रा पूर्ति बढ़ाती है तो यह भी अल्पकाल में अप्रभावी रहती है। ऐसी नीति तभी अल्पकाल में बेरोजगारी कम कर सकती है जब अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पूर्वानुमानित न हों। परन्तु जब सरकार इस तरह की विस्तारक मौद्रिक नीति पर डटी रहती है तो लोगों को स्फीति दर में वृद्धि की प्रत्याशा हो जाती है। फर्म अपनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देती हैं जिससे सम्भावित स्फीति को निष्क्रिय बनाया जा सके ताकि उत्पादन पर उसका कोई प्रभाव न हो। इसी प्रकार, स्फीति में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हुए वर्कर अधिक वेतन की मांग करते हैं तथा फर्म और अधिक वर्करो को रोजगार नहीं देती हैं। अतः इससे बेरोजगारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

इस प्रकार देखा जाय तो रेटेक्स परिकल्पना यह सुझाती है कि विस्तारक राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां बेरोजगारी पर अस्थायी प्रभाव डालेंगी और यदि चलती रहें तो स्फीति तथा बेरोजगारी में और वृद्धि कर सकती हैं। ऐसी नीतियों की सफलता तभी है जब लोग इनका पूर्वानुमान न लगा सकें। एक बार जब लोग उनका पूर्वानुमान लगा लेते हैं तो स्वयं को उसके अनुसार ढाल लेते हैं तो अर्थव्यवस्था अपनी पुणनी बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर लौट आती है। अतः विस्तारक राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों के बेरोजगारी पर अल्पकालिक प्रभाव के लिए सरकार को लोगों को मूर्ख बनाना होगा। परन्तु हमेशा ऐसा नहीं होता। यदि सरकार इन नीतियों को लागू रखती है तो वे अप्रभावी हो जाती हैं क्योंकि लोगों को अधिक समय तक मूर्ख बनाना कठिन है और वे उत्पादन तथा बेरोजगारी पर इसके प्रभाव का पूर्वानुमान लगा देते हैं। इस प्रकार, राजकोषीय मौद्रिक नीतियां अल्पकाल में अप्रभावी हो जाती हैं। रेटेक्स परिकल्पनाओं का समर्थन करने वालों के अनुसार व्यापक बेरोजगारी किए बिना स्फीति को नियन्त्रित किया जा सकता है, यदि सरकार राजकोषीय तथा मौद्रिक उपायों की घोषणा करे तथा लोगों को आश्चर्यचकित करने की बजाय उन्हें इसके बारे में समझाए।

आलोचनाएं (Criticisms)

रेटेक्स परिकल्पना की अर्थशास्त्रियों ने निम्न आधार पर आलोचना की है—

1. **अवास्तविक मान्यता (Unrealistic Assumption)**—विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की मान्यता अवास्तविक है। आलोचकों का तर्क है कि बड़ी फर्में तो सही-सही अनुमान लगा पाएंगी परन्तु छोटी फर्में अथवा एक सामान्य कर्मचारी ऐसा नहीं कर पाएगा।
2. **महंगी सूचना (Costly Information)**—सूचना एकत्र करना, उसका विश्लेषण तथा प्रसार बहुत महंगा है। अतः सूचना के लिए उचित बाजार नहीं है। इसलिए अधिकांश आर्थिक एजेंट विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं के आधार पर काम नहीं कर सकते।
3. **भिन्न सूचना (Different Information)**—आलोचकों का यह भी मानना है कि सरकार को उपलब्ध सूचना, फर्मों तथा वर्कर्स को मिली सूचना से भिन्न होती है। तदनुसार फर्मों तथा वर्कर्स की स्फीति की संभावित दर के बारे में प्रत्याशाएं जरूरी नहीं कि केवल अविचारित (random) त्रुटि के कारण ही वास्तविक दर से भिन्न हों। परन्तु सरकार उपलब्ध सूचना के आधार पर स्फीति की संभावित तथा वास्तविक दर से बीच के अन्तर के बारे में सही-सही पूर्वानुमान लगा सकती है।
4. **कीमतें और मजदूरियां लचीली नहीं (Prices and Wages not Flexible)**—यद्यपि सरकार तथा व्यक्तियों दोनों की सूचनाओं तक पहुंच बराबर है तथापि इस बात की गारंटी नहीं है कि उनकी प्रत्याशाएं विवेकपूर्ण होंगी। आलोचकों का कहना है कि कीमतें तथा मजदूरियां लचीली नहीं हैं। फिलिप्स, टेलर तथा फिशर जैसे अर्थशास्त्रियों ने यह दर्शाया है कि यदि मजदूरियां तथा कीमतें स्थिर हैं तो मौद्रिक अथवा राजकोषीय नीतियां अल्पकाल में भी प्रभावी हो जाती हैं। मजदूरी दरों की स्थिरता का अर्थ है कि वे बाजारी शक्तियों के साथ अपेक्षाकृत धीमे रूप से समायोजन करती हैं क्योंकि मजदूरी अनुबन्ध एक बार में दो-तीन वर्षों के लिए लागू होते हैं। इसी प्रकार, अवधि के आरंभ से संभावित कीमतों की दर की अवधि के अन्त तक बने रहने की अपेक्षा की जाती है। अतः यदि प्रत्याशाएं विवेकपूर्ण भी हों तो मौद्रिक अथवा राजकोषीय नीतियां उत्पादन तथा बेरोजगारी को अल्पकाल में प्रभावित कर सकती हैं।
5. **प्रत्याशाएं अनुकूली (Expectations Adaptive)**—गोर्डन ने रेटेक्स परिकल्पना के तर्क को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। उसने दो कारण बताए हैं: पहला, कोई व्यक्ति विशेष बाजार समाशोधन कीमतों के स्तर का अनुमान लगाने के लिए अर्थव्यवस्था के ढांचे के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखता तथा अनुकूली प्रत्याशाओं से चिपका रहता है। दूसरा, यदि वह किसी तरह अर्थव्यवस्था के ढांचे के बारे में धीरे-धीरे सीख भी जाता है तो विवेकपूर्ण प्रत्याशाएं अनुकूली प्रत्याशाओं के बहुत समीप होंगी।
6. **सरकार असमर्थ नहीं (Government not Impotent)**—प्रायः यह कहा जाता है कि रेटेक्स परिकल्पना के अनुसार सरकार आर्थिक क्षेत्र में असमर्थ है। परन्तु रेटेक्स अर्थशास्त्री ऐसा नहीं मानते। बल्कि उनका विश्वास है कि सरकार आर्थिक नीतियों पर गहरा प्रभाव डालती है।

प्रश्न

1. विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की परिकल्पना की मूल प्रस्थापनाओं की व्याख्या कीजिए।
2. "विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं के अन्तर्गत स्थिरीकरण की नीति अल्पकाल में अप्रभावी होती है।" इस कथन को विवेचना कीजिए।
3. अनुकूली प्रत्याशाओं पर टिप्पणी लिखिए।